

आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक-12 जून 2024

7:20 AM

पहले मुख्य समाचार।

- केंद्र ने आर्थिक विकास के लिए राज्यों को एक लाख 39 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी : उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली।
- तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अट्टारह जून को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी देने समेत 41 प्रस्ताव पारित। कल हुई मंत्री परिषद की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर लगी मुहर।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में अगले शैक्षणिक सत्र से वर्ष में दो बार हो सकेगा प्रवेश। यूजीसी ने छात्र हितों को देखते हुए लिया नीतिगत निर्णय।

केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को एक लाख उनतालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर धनराशि जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह राशि राज्य सरकारों को विकास और पूंजी संबंधी व्यय में तेजी लाने में सहायता करेगी। जारी धनराशि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक, बिहार को 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक, मध्य प्रदेश को लगभग 11 हजार करोड़ और पश्चिम बंगाल को 10 हजार पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है। इस किस्त के साथ ही अब तक केंद्र सरकार ने 10 जून 2024 तक राज्यों को दो लाख उन्यासी हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कर दिया है। वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए लगभग बारह लाख 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसके अतिरिक्त, जून 2024 में धनराशि की एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी।

मोदी सरकार के ज्यादातर मंत्रियों ने विभाग आवंटन के बाद कल कार्यभार ग्रहण कर लिया। केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, निर्मला सीतारमन को वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्री के पद पर बरकरार रखा है। पेश है एक रिपोर्ट...

जगत प्रकाश नड्डा नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय आवंटित किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा जाधव प्रतापराव गणपतराव को आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को कौशल विकास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, उन्हें शिक्षा राज्यमंत्री भी बनाया गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ, समाचार कक्ष से, मुकेश कुमार बल।

केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद श्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली बार अक्टूबर जून को आएंगे। अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वह वाराणसी में किसान सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि किसान सम्मेलन को सम्बोधित करने के बाद प्रधानमंत्री श्रीकाशी विश्वनाथ का दर्शन-पूजन करेंगे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले शैक्षणिक वर्ष से साल में छात्रों को दो बार प्रवेश देने की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लिया है। वर्तमान में यूजीसी एक वर्ष में एक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देता है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि इससे उन छात्रों को अधिक फायदा मिलेगा, जिनके बोर्ड परिणामों की घोषणा में देरी हो जाती है या जो स्वास्थ्य समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से प्रवेश लेने से चूक जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-नीट स्नातक 2024 के बाद मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 05 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी- एन टी ए और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले को एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़कर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल रायबरेली पहुंचकर आभार सभा को संबोधित किया। अमेठी और रायबरेली सीट पर जीत के लिए जनता का आभार जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के चुनाव में जनता ने हिंसा, झूठ और अहंकार के खिलाफ वोट किया है। भाजपा के लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे थे पर जनता ने उन्हें संविधान को माथे से लगाने के लिए मजबूर कर दिया है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली व अमेठी लोकसभा सीट पर जीत कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इस जीत से साबित हो गया है कि प्रदेश व देश के लोग साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। इस मौके पर अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी देने समेत 41 प्रस्तावों को पारित किया गया।

मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्थानांतरण नीति 2024-25 के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत, वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं। बैठक में बुंदेलखंड के झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर और मिर्जापुर, सोनभद्र जनपदों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण कराने पर मुहर लगी है। सरकार ने प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों के नामों में भी मामूली संशोधन किया है।

श्री खन्ना ने बताया कि जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, उनमें औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास, गृह विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि और चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर नीति का प्रस्ताव, औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव का प्रस्ताव बैठक में पास हुआ है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जिन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है उनमें नोएडा का 500 बेड वाला अस्पताल, आईआईटी कानपुर 500 बेड वाला एमएमटी 750 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इसमें केन्द्रीय बजट से स्कूल ऑफ रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी के रूप में तैयार किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में 50 करोड़ के अंशदान देगी। वहीं लखीमपुर हवाई अड्डे के विस्तार को स्वीकृत मिली है। इसमें तीन गांवों की जमीन को किसानों से लिया जाएगा। प्रदेश सरकार के जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट 30 जून और 31 दिसम्बर को हुआ है और उनकी एक जुलाई को ग्रेच्युटी लागू है उसे लाभ दिया जाएगा।

एक जुलाई 2024 से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू होने वाले नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, जवाबदेह, भरोसेमंद और न्याय प्रेरित बनाने का प्रयास हैं। मुरादाबाद स्थित उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केपी मिश्रा ने आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी से खास बातचीत में कहा कि नए कानूनों के लागू होने से आम जन को जल्द से जल्द न्याय मिल सकेगा। अब किसी प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी।

हमारी अभी तक न्याय प्रणाली में ये था कि लोगों का बहुत देर से न्याय मिलता था। जो सबसे बड़ा एक बियनेस के अलावा बीएनएसएस आ गया है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेगे उसमें आ गया है। अब लोगों को बिल्कुल समय से न्याय मिलेगा। मतलब मजिस्ट्रेटों कोर्टों के लिए अब समयबद्धता कर दिया गया है। अब ये नहीं की मनमानी नहीं चलेगी कि कोर्ट जब चाहे जब जजमेंट सुनाये जब चाहे न सुनाये सब समयबद्धता टाईम बाउंड पूरा कर दिया गया है। उन सभी व्यक्तियों को कि पुलिस इतने समय में चार्जशीट भेजेगी। कोर्ट इतने समय में इसको संज्ञान लेगी इतने दिनों के अंदर आगुमेंट करेगी और जैसे तीस से पैंतालीस दिनों के अंदर उसको निर्णय देगी।
